दी नेक्स्ट पोस्ट

साप्ताहिक

7 | 3 नेटवर्क मार्केटिंग का जाल | 5 500 झुग्गियों में लगी भीषण आग | 8 सत्र की पहली जीत को तरसी केकेआर

UPHIN/2023/90814 | वर्ष: 03, अंक: 43 | पृष्ठ संख्या: 8 | मूल्य: 1.00 रू. | सोमवार 20 अप्रैल, 2026

महिला आरक्षण

झटका: संविधान संशोधन बिल के पक्ष में 298, विरोध में 230 वोट

गणित: बिल पास होने के लिए दो तिहाई यानी 352 वोट चाहिए थे

असर: आरक्षण जनगणना के बाद ही लागू होगा यानी 2034 से पहले नहीं

ना...री! आरक्षण 2029 से तो नहीं मिलेगा

संसद में दिखे हल्के-फुल्के पल

24 साल बाद कोई सरकारी बिल गिरा

- 2002 के आतंकवाद निवारण बिल (पोटा) के बाद संसद में पराजित होने वाला पहला सरकारी विधेयक है।
- 1990 के संविधान (64वां संशोधन) बिल के बाद लोकसभा में गिरने वाला पहला संविधान संशोधन विधेयक है।

30 साल में 7वीं बार महिलाओं को झटका

- पिछले 30 साल (1996 से 2026) में 7वीं बार ऐसा हुआ है, जब महिला आरक्षण मिलने से पहले अटक गया...

वर्ष	सरकार	मुख्य रोड़ा / कारण
1996	देवेगौड़ा	लोकसभा भंग होने से बिल गिरा
1998	वाजपेयी	हंगामा; सांसद ने बिल फाड़ दिया
1999	वाजपेयी	'कोटे में कोटा' पर असहमति
2002-03	वाजपेयी	क्षेत्रीय दलों का विरोध, वोटिंग नहीं
2008-10	मनमोहन	लोस में वोटिंग नहीं; बिल लैप्स
2023	मोदी	पारित, लेकिन नई जनगणना व परिसीमन की शर्त
2026	मोदी	17 अप्रैल, 2/3 बहुमत न मिलने से बिल गिर गया

महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिरना NDA की पहली लेजिस्लेटिव हार

नई दिल्ली,एजेंसी

महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष की एकजुटता ने बीजेपी के नेतृत्व वाली **NDA** सरकार के अरमानों पर पानी फेर दिया और लोकसभा में ही 'नारी शक्ति वंदन' अधिनियम गिर गया। विपक्ष ने पीएम नरेंद्र मोदी की 'अंतरात्मा की आवाज पर वोट' देने की आखिरी मिनट की अपील को ठुकरा दिया। गृह मंत्री शाह के उस प्रस्ताव पर भी विपक्ष ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जिसमें महिला आरक्षण बिल में यह जोड़ने की बात कही गई थी कि सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या 50 फीसदी बढ़ जाएगी। विपक्ष ने सरकार को 12 सालों में पहली बार विधायी मोर्चे पर हार का सामना करने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि प्रस्तावित कानून सदन में जरूरी दो–तिहाई वोट हासिल करने में नाकाम रहा।

महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास नहल हो सका। बिल पर वोटिंग के दौरान इतने वोट नहीं मिल सके कि वह लोकसभा में पास हो सके। हालांकि, वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी सांसदों से अंतरात्मा की आवाज सुनने की अपील की, लेकिन विपक्ष की एकजुटता के कारण एनडीए सरकार का यह बिल निचले सदन में ही ढेर हो गया।

पक्ष में कितने और विपक्ष में कितने वोट

संविधान (131वां संशोधन) विधेयक के समर्थन में 298 वोट पड़े और विरोध में 230 वोट।

ये जीत तो सिर्फ ट्रेलर है : स्टालिन

जो बिल तमिलनाडु के खिलाफ आया था, वह संसद में हार गया है। यह जीत तो बस एक ट्रेलर है। अगला चुनाव आने वाला है। यह 'तमिलनाडु बनाम दिल्ली' की लड़ाई है। हम 200 से अधिक सीटें जीतने जा रहे हैं। **- एमके स्टालिन,** मुख्यमंत्री, तमिलनाडु

विपक्ष 'महिला विरोधी' है : राजनाथ

भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आज (17 अप्रैल) का दिन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन ने लोकसभा में महिला बिल के खिलाफ वोटिंग करके अपना महिला-विरोधी चरित्र उजागर कर दिया है। **- राजनाथ सिंह,** रक्षा मंत्री

ओबीसी शामिल ही नहीं थे : प्रियंका

पुरानी जनगणना के आधार पर परिसीमन करके महिला आरक्षण लागू करना गलत था, खासकर तब जब उसमें ओबीसी वर्ग को शामिल नहीं किया गया। इस वजह से कांग्रेस इस बिल का समर्थन नहीं कर सकती थी। **- प्रियंका गांधी वाड्रा,** कांग्रेस सांसद

दुनिया में सबसे अमीर इलॉन मस्क, एशिया में गौतम अदाणी

SWIPE कर देखें एशिया और दुनिया के TOP अमीरों की लिस्ट

एशिया में टॉप पर अदाणी-अंबानी

गौतम अदाणी
₹8.5 लाख करोड़

मुकेश अंबानी
₹8.4 लाख करोड़

झोंग शानशान
₹5.7 लाख करोड़

कॉलिन हुआंग
₹4.7 लाख करोड़

मा हुआतेंग
₹4.5 लाख करोड़

SOURCE : Bloomberg Billionaires Index

'जन समस्याओं का त्वरित समाधान कराएं अधिकारी', सीएम ने दिए निर्देश

गोरखपुर,संवाददाता। गोरखनाथ मंदिर परिसर में, महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी करीब 200 लोगों से मिले। उनके पास जाकर उनकी बातें सुनीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लगातार दूसरे दिन, गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता की समस्याओं पर त्वरित संवेदनशीलता दिखाएं। समस्या से जुड़ी शिकायत पर तेजी से कार्रवाई करते हुए गुणवत्तापूर्ण व संतुष्टिपरक समाधान सुनिश्चित कराएं। जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को मुख्यमंत्री ने आश्वस्त करते हुए कहा, 'घबराइए मत। सरकार, आपकी हर समस्या पर प्रभावी समाधान सुनिश्चित कराएगी।'

शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में, महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी करीब 200 लोगों से मिले। उनके पास जाकर उनकी बातें सुनीं। उनके प्रार्थना पत्र लेकर उसका अवलोकन कर समस्या/शिकायत का संज्ञान लिया। फिर, अलग–अलग मामलों से जुड़ी समस्याओं के निस्तारण के लिए उन्होंने संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र संदर्भित और हस्तगत किया। साथ ही निर्देश दिया कि सभी समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और संतुष्टिप्रद होना चाहिए।

सीएम ने जनता दर्शन में 200 लोगों की सुनी समस्या

जनता दर्शन में हर बार की तरह कुछ लोग इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिया कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि जो भी जरूरतमंद हैं, प्रशासन उनके उच्च स्तरीय इलाज का इस्टीमेट शीघ्रता से बनवाकर उपलब्ध कराए।

इस्टीमेट मिलते ही सरकार धन उपलब्ध कराएगी। कुछ महिलाओं ने आवास की समस्या मुख्यमंत्री को बताई। इस पर सीएम योगी ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार हर जरूरतमंद को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का आवास उपलब्ध कराने को संकल्पित हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी पात्र लोग पक्के आवास की सुविधा से वंचित हैं, उन्हें इसका लाभ दिलाया जाए।

PM नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, ट्रंप टॉप 10 में भी नहीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जगह मिली है. अमेरिका की डेटा एनालिटिक्स कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट के ताजा सर्वे में उन्हें 68 फीसदी अप्रूवल रेटिंग मिली है. वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 39 फीसदी अप्रूवल रेटिंग मिली और वे टॉप 10 में जगह नहीं बना पाए।

हमने अपना पक्ष साफ रखा है. हम महिला आरक्षण के पक्ष में है, महिलाओं को आरक्षण मिले, उन्हें सुरक्षा मिले, उनका सम्मान बढ़े, लोकतंत्र में जो उनको स्थान मिलना चाहिए, हम उसके पक्ष में हैं. समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने महिला आरक्षण को लेकर विरोध नहीं किया लेकिन उसके साथ ये जो महिलाओं के अधिकारों का हरण करना चाहते थे, विपक्ष ने ऐसी लक्ष्मण रेखा खींची कि वे उस लक्ष्मण रेखा के पार नहीं आ पाए.

अखिलेश यादव
सपा प्रमुख

अपर्णा यादव ने जला दिया समाजवादी पार्टी का झंडा, बोलीं- मैं इन विधर्मियों को बताने आई हूं

खुशखबरी: रूस से सस्ता तेल खरीदता रहेगा भारत, अमेरिका का ऐलान, ट्रंप प्रशासन का बड़ा यूटर्न

उत्तर बंगाल का 'चक्रव्यूह' 54 सीटों पर BJP के सामने किला बचाने की चुनौती, 'दीदी' की ब्रिगेड सेंधमारी को तैयार

भारत की महिलाओं को जो अधिकार देना था, वह नहीं देने पर अगर कांग्रेस जश्न मना रही है तो इससे दुखद कुछ और नहीं हो सकता... भारत की महिलाएं कभी भी कांग्रेस और विपक्ष को माफ नहीं करेंगी. कांग्रेस की मंशा साफ थी कि महिलाओं को आरक्षण न मिले... कांग्रेस बेनकाब हो गई है. हम महिलाओं का अधिकार उन्हें दिलाकर रहेंगे.

किरेन रीजीजू
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री

सम्पादकीय

महिला हित की अनदेखी, फिर से ठंडे बस्ते में चला गया आरक्षण

महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में बहुमत के अभाव में विफल।
अब 2034 से पहले लागू होने की संभावना कम।
विपक्ष ने सरकार के सीट वृद्धि प्रस्ताव को अस्वीकारा।

अंततः जिसका अंदेशा था, वही हुआ। महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक दो तिहाई बहुमत के अभाव में लोकसभा से पारित नहीं हो सका। इसी के साथ एक तरह से महिला आरक्षण फिर से ठंडे बस्ते में चला गया। कहना कठिन है कि अब वह कब लागू हो सकेगा। यदि पक्ष–विपक्ष के बीच निकट भविष्य में कोई सहमति नहीं बनती तो आसार यही हैं कि महिला आरक्षण 2034 के लोकसभा चुनाव के पहले क्रियान्वित नहीं हो सकता। महिला आरक्षण में और अधिक देरी दुर्भाग्य की ही बात होगी। ध्यान रहे महिला आरक्षण के सपने को साकार करने में पहले ही बहुत देर हो चुकी है। महिला आरक्षण का विचार करीब तीन दशक पहले राजनीतिक विमर्श का विषय बना था। इसके बाद सभी दल महिला आरक्षण के पक्ष में बातें तो करते रहे, लेकिन वे उसके लिए मन से तैयार नहीं हुए। इसी कारण महिला आरक्षण संबंधी विधेयक कई बार संसद में पेश होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ सका।

अंततः 2023 में वह सभी दलों की सहमति से परित तो हुआ, पर इस प्रविधान के साथ कि उसे 2029 के आम चुनाव में लागू किया जाएगा। इसका कारण 2021 में होने वाली जनगणना में विलंब होना रहा। चूंकि नई जनगणना अब जाकर शुरू हुई है और उसके नतीजे आने में समय लगेगा, इसलिए मोदी सरकार ने अगले आम चुनावों से ही महिला आरक्षण को प्रभावी बनाने और विपक्ष की आपत्तियों को दूर करने के लिए यह फार्मूला रखा कि सभी राज्यों की लोकसभा सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि करके महिला आरक्षण को लागू किया जाए।

पता नहीं क्यों विपक्ष को सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत की वृद्धि का फार्मूला रास नहीं आया, जबकि इससे किसी भी राज्य और विशेष रूप से दक्षिण के राज्यों के राजनीतिक हितों की कोई क्षति नहीं होने जा रही थी। अच्छा होता कि विपक्ष नई जनगणना और उस पर आधारित परिसीमन के आधार पर महिला आरक्षण लागू करने की अपनी जिद का परित्याग करता, क्योंकि यदि जनसंख्या के आधार पर महिला आरक्षण लागू किया जाता है तो कम आबादी वाले दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के राज्य तो राजनीतिक रूप से नुकसान में ही रहेंगे। जहां तक विपक्ष की यह मांग है कि महिला आरक्षण में विभिन्न वर्गों के लिए अलग से आरक्षण लागू किया जाए तो इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि 2023 में ऐसी कोई मांग नहीं की गई थी। महिला आरक्षण संबंधी संशोधन विधेयक पारित न होने से विपक्ष अपनी जीत की घोषणा अवश्य करेगा, लेकिन ऐसा करके वह देश की महिलाओं को मायूस ही करेगा। निश्चित रूप से सत्ता पक्ष को झटका लगा है, लेकिन उसे यह प्रचार करने का अवसर हाथ भी लगा है कि विपक्ष ने महिला आरक्षण लागू नहीं होने दिया और इस तरह आधी आबादी की आशाओं पर तुषारापात किया।

महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में दो–तिहाई बहुमत न मिलने के कारण पारित नहीं हो सका, जिससे यह फिर से ठंडे बस्ते में चला गया है। अब इसके 2034 से पहले लागू होने की संभावना कम है।

परिसीमन पर सवाल–संदेह

भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई.कुरैशी की चेतावनी है कि यदि परिसीमन के भरोसे रहे, तो 2034 के आम चुनाव तक महिला आरक्षण कानून लागू हो पाएगा। यदि महिलाओं को राजनीतिक और नीति–निर्धारण में भागीदारी देनी है, तो 50 फीसदी के फॉर्मूले के आधार पर उतनी ही सीटें आवंटित की जा सकती हैं। मसलन–भाजपा–एनडीए को चुनाव में जो जनादेश प्राप्त हुआ था, उसके मुताबिक लोकसभा में उनकी कुल 292 सीटें हैं। उसमें 50 फीसदी, यानी 146, सीटें जोड़ कर उन सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जा सकता है। इसी तरह विपक्ष की 233 सीटों में 116 सीटें और जोड़ी जा सकती हैं। चूंकि संशोधन बिल के मुताबिक, लोकसभा में 543 से बढ़ कर 815 सीटें हो जाएंगी और 33 फीसदी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यानी सदन में 273 महिलाएं सांसद बनकर आ सकेंगी। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का आकलन है कि जो जनगणना शुरू हुई है, वह 2027 तक जारी रहेगी। उसके नतीजे आने और संकलित होने में इतना वक्त खर्च होना मुमकिन है कि 2029 के आम चुनाव करीब खड़े दिखाई देंगे। यदि 2011 की 121 करोड़ से अधिक जनसंख्या के आधार पर परिसीमन तय किया गया है या किया जाना है, तो वह बुनियादी तौर पर विसंगत होगा, समानुपाती नहीं होगा, क्योंकि देश की मौजूदा आबादी 147.66 करोड़ से अधिक है। क्या दोनों जनगणनाओं में अंतर नहीं है? क्या पुरानी जनसंख्या के आधार पर मौजूदा आबादी के विकास, विस्तार, भौगोलिक बदलावों का परिसीमन किया जा सकता है? परिसीमन सरकार की मनमर्जी के मुताबिक नहीं होना चाहिए। बेशक परिसीमन आयोग सर्वोच्च अदालत के वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित होता है और उसके निष्कर्षों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। फिर भी आयोग की रपट पर पहले संसद की स्वीकृति अनिवार्य है और फिर राष्ट्रपति की मुहर अंतिम निर्णय है। देश के जम्मू–कश्मीर और असम के कुछ मामले, परिसीमन के बाद, सामने आए हैं, जो इतने असंतुलित और असमान हैं कि परिसीमन की ईमानदारी पर ढेरों सवाल और संदेह किए जा सकते हैं। 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पर जो संविधान संशोधन लोकसभा में पेश किया गया था, उस पर मत–विभाजन हो चुका होगा अथवा विपक्ष ने सामूहिक बहिर्गमन का रास्ता चुना होगा! इसका विश्लेषण बाद में करेंगे, क्योंकि यह घटनाक्रम शुक्रवार शाम तक होना था। बहरहाल इस संविधान संशोधन से पहले ही, गुरुवार देर रात्रि, 2023 में पारित किए गए कानून की सरकारी अधिसूचना भी जारी कर दी गई।

इसके क्या 'तकनीकी कारण' हो सकते हैं? यह लोकतंत्र और संसद का अपमान है, क्योंकि महिला आरक्षण पर संसद में बहस जारी थी। अभी तक की चर्चा में कांग्रेस, सपा, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, सीपीएम आदि विपक्षी दलों ने सतही तौर पर महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया, लेकिन परिसीमन के जरिए संघीयवाद, लोकतंत्र के उल्लंघन पर सवाल और संदेह जरूर किए। हम आज तक समझ नहीं पाए हैं कि विपक्ष दिन में कितनी बार 'लोकतंत्र की हत्या' मान लेता है और फिर उसी लोकतंत्र की आड़ में छिप कर राजनीति भी करने लगता है? बहरहाल लोकतंत्र कभी नहीं मरता, लेकिन जो व्यवस्थाएं मौजूद हैं, जो विसंगतियां हमें खोखला कर रही हैं, वे जरूर बदलनी चाहिए। लोकसभा में फिलहाल 74–75 महिला सांसद हैं। उनका प्रतिनिधित्व 13.6 फीसदी बनता है। राज्यसभा में भी यह औसत करीब 17 फीसदी है और महिला सांसद 41 हैं। यदि महिला आरक्षण कानून, अंततः, लागू होता है, तो राज्यों की विधानसभाओं में विधायकों की संख्या 4123 से बढ़ कर 6186 हो जाएगी। पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक, स्थानीय नगर निकायों में हजारों महिलाएं सक्रिय हैं। उन्हें प्रशासनिक अनुभव भी हासिल हो रहा है। वे अब 'गूंगी गुडिया' नहीं, मासूम नहीं हैं, बल्कि राजनीतिक चेतना और जागृति से भरपूर हैं। देश की 'आधी जन–शक्ति' को संसद, विधानसभा के स्तर पर भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन मायनों में यह कानून वाकई एक क्रांतिकारी, ऐतिहासिक कदम, मील–पत्थर साबित हो सकता है। इस बदलाव को रोका नहीं जाना चाहिए।

न्यायपालिका की विश्वसनीयता का प्रश्न

भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे न्यायाधीश यशवंत वर्मा के इस्तीफे ने न्यायपालिका की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। महाभियोग प्रक्रिया की जटिलता के कारण न्यायाधीश अक्सर कार्रवाई से बचने के लिए इस्तीफा दे देते हैं, जिससे आम जनता का विश्वास कमजोर होता है। हरबंश दीक्षित। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा ने अपने खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया शुरू होने के बीच त्यागपत्र दे दिया। उनके घर करोड़ों के अधजले नोट मिले थे और सुप्रीम कोर्ट की एक समिति ने उन्हें दोषी पाया था। उनके त्यागपत्र देने से अब उनके ऊपर महाभियोग की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ेगी। हो सकता है कि अब उनके ऊपर कोई मुकदमा भी नहीं चले। त्यागपत्र के इस घटनाक्रम ने संविधान के भरोसे, उसकी बेचारगी और आम नागरिक के विश्वास से जुड़े गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। हमारे पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं कि जिस अपराध के लिए आम आदमी से मुख्यमंत्री तक को जेल जाना पड़ता है, आखिर उसी तरह के अपराध के लिए उस संस्था का जिम्मेदार अधिकारी, जिसकी सत्यनिष्ठा की हम कसमें खाते हैं, वह केवल त्यागपत्र देकर दोषमुक्त कैसे हो सकता है? यह घटनाक्रम केवल एक व्यक्ति या पद तक सीमित नहीं है। यह उस संस्थागत विश्वास से जुड़ा प्रश्न है, जिसके आधार पर आम जन न्यायपालिका को न्याय का अंतिम, निष्पक्ष और नैतिक मंच मानता है। जब इस मंच की निष्पक्षता और उत्तरदायित्व पर प्रश्नचिह्न लगता है तो उसका प्रभाव पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर पड़ता है।

महाभियोग ही न्यायाधीशों के विरुद्ध कार्रवाई का एकमात्र संवैधानिक माध्यम है। यह प्रक्रिया जानबूझकर कठिन बनाई गई, ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप न हो, किंतु व्यवहार में यही जटिलता कई बार जवाबदेही के मार्ग में बाधा बन जाती है। संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता, राजनीतिक सहमति का अभाव और लंबी प्रक्रियात्मक जटिलता के कारण महाभियोग लगभग अप्राप्य प्रक्रिया बनकर रह गया है। अभी तक महाभियोग के जरिए उच्चतर न्यायपालिका के किसी भी न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सका है, जबकि कई न्यायाधीश कदाचार के गंभीर आरोपों से घिरे रहे।

अधिकांश मामलों में यही देखने को मिला है कि जैसे ही महाभियोग की संभावना प्रबल होती है, आरोपों से घिरा संबंधित न्यायाधीश त्यागपत्र देकर प्रक्रिया को निष्प्रभावी कर देते हैं और यहीं से उत्तरदायित्व का संकट उत्पन्न होता है। भारतीय न्यायिक इतिहास में इसके कई उदाहरण मिलते हैं, जो इस समस्या की संरचनात्मक प्रकृति को उजागर करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी के विरुद्ध 1990 के दशक में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, किंतु लोकसभा में आवश्यक समर्थन न मिलने के कारण वह पारित नहीं हो सका। इसका कारण यह रहा कि कई राजनीतिक दलों ने क्षेत्रीयता का सवाल उठाकर उन्हें महाभियोग की प्रक्रिया से हटाने के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। इसके पश्चात कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस सौमित्र सेन के विरुद्ध राज्यसभा ने महाभियोग प्रस्ताव पारित कर दिया था, जो भारतीय संसदीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, किंतु लोकसभा में अंतिम निर्णय से पूर्व ही उनके त्यागपत्र देने से पूरी प्रक्रिया अधूरी रह गई। इसी प्रकार कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पी. दिनकरन ने भी गंभीर आरोपों के बीच पद त्याग कर दिया, जिससे उनके विरुद्ध चल रही महाभियोग की कार्यवाही स्वतः समाप्त हो गई। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि त्यागपत्र कई बार एक प्रकार का 'संवैधानिक निकास मार्ग' बन जाता है, जिससे अंतिम उत्तरदायित्व सुनिश्चित नहीं हो पाता। यह स्थिति कई प्रश्न खड़े करती है कि क्या त्यागपत्र देना ही पर्याप्त जवाबदेही है? क्या यह न्यायपालिका की गरिमा की रक्षा करता है या केवल संस्थागत असहजता से बचने का एक औपचारिक उपाय है? क्या इससे आम नागरिक के मन में यह धारणा नहीं बनती कि उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों के लिए अलग मानदंड हैं?

न्यायपालिका की सबसे बड़ी शक्ति उसकी नैतिक विश्वसनीयता है। यदि वही प्रश्नों के घेरे में आ जाए तो संवैधानिक व्यवस्था की स्थिरता भी प्रभावित हो सकती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी जवाबदेही, दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। यदि स्वतंत्रता के नाम पर जवाबदेही को कमजोर किया जाता है तो यह लोकतंत्र के लिए उतना ही खतरनाक है, जितना कि अत्यधिक हस्तक्षेप। अतः आवश्यकता इस संतुलन को पुनर्स्थापित करने की है। इसके समाधान के लिए कुछ सुझावों पर विचार किया जा सकता है। प्रथम, महाभियोग प्रक्रिया को अधिक व्यावहारिक और समयबद्ध बनाया जाए, ताकि यह केवल एक सैद्धांतिक प्रविधान न रह जाए। दूसरा, यह कि एक स्वतंत्र और पारदर्शी न्यायिक आचार आयोग की स्थापना की जाए, जो न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों की प्रारंभिक जांच कर सके और आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा कर सके। तृतीय, यह सुनिश्चित किया जाए कि त्यागपत्र देने के बाद भी यदि आरोप आपराधिक प्रकृति के हों तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध सामान्य विधिक प्रक्रिया के तहत जांच और अभियोजन जारी रह सके। न्यायपालिका से जुड़ा होना दंड से मुक्ति का आधार नहीं बन सकता। इसके अतिरिक्त पारदर्शिता और जन–विश्वास को सुदृढ़ करने के लिए न्यायपालिका को अपने आंतरिक तंत्रों को अधिक उत्तरदायी बनाना होगा। न्यायाधीश यशवंत वर्मा का मामला केवल एक न्यायाधीश या एक प्रकरण का प्रश्न नहीं है, बल्कि उस विश्वास का है, जो करोड़ों भारतीयों ने न्यायपालिका में रखा है। लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति उसकी संस्थाओं में नहीं, बल्कि उन संस्थाओं में जनता के विश्वास में निहित होती है। यदि यह विश्वास कमजोर होता है तो संविधान का आत्मा भी आहत होता है। आज आवश्यकता केवल आलोचना की नहीं, बल्कि आत्ममंथन और संस्थागत सुधार की है। न्यायपालिका की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए, उसे और अधिक उत्तरदायी बनाना समय की मांग है। तभी यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि न्याय के मानक सभी के लिए समान रूप से लागू हों, बिना किसी अपवाद और विशेषाधिकार के। यही वह कसौटी है जिस पर किसी भी लोकतंत्र की परिपक्वता और विश्वसनीयता का वास्तविक आकलन किया जाता है।

न्यायपालिका की सबसे बड़ी शक्ति उसकी नैतिक विश्वसनीयता है। यदि वही प्रश्नों के घेरे में आ जाए तो संवैधानिक व्यवस्था की स्थिरता भी प्रभावित हो सकती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी जवाबदेही, दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। यदि स्वतंत्रता के नाम पर जवाबदेही को कमजोर किया जाता है तो यह लोकतंत्र के लिए उतना ही खतरनाक है, जितना कि अत्यधिक हस्तक्षेप। अतः आवश्यकता इस संतुलन को पुनर्स्थापित करने की है। इसके समाधान के लिए कुछ सुझावों पर विचार किया जा सकता है। प्रथम, महाभियोग प्रक्रिया को अधिक व्यावहारिक और समयबद्ध बनाया जाए, ताकि यह केवल एक सैद्धांतिक प्रविधान न रह जाए।

दूसरा, यह कि एक स्वतंत्र और पारदर्शी न्यायिक आचार आयोग की स्थापना की जाए, जो न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों की प्रारंभिक जांच कर सके और आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा कर सके। तृतीय, यह सुनिश्चित किया जाए कि त्यागपत्र देने के बाद भी यदि आरोप आपराधिक प्रकृति के हों तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध सामान्य विधिक प्रक्रिया के तहत जांच और अभियोजन जारी रह सके। न्यायपालिका से जुड़ा होना दंड से मुक्ति का आधार नहीं बन सकता। इसके अतिरिक्त पारदर्शिता और जन–विश्वास को सुदृढ़ करने के लिए न्यायपालिका को अपने आंतरिक तंत्रों को अधिक उत्तरदायी बनाना होगा।

सीएम योगी बोले- सुशासन की पहली शर्त होती है सुरक्षा
समय पर पुलिस भर्ती, टनिंग से बना बेहतर माहौल

गोरखपुर,संवाददाता। सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बने दो आधुनिक सुरक्षा भवनों के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इन भवनों में मंदिर सुरक्षा से जुड़े अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय, कंट्रोल रूम, पुलिस स्टोर रूम और मेंटिनेंस वर्कशाप बनाए गए हैं। इसके निर्माण पर 9.18 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आई है। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा भवन का लोकार्पण करने के बाद भ्रमण और निरीक्षण कर भवन में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद पुलिस विभाग में समय पर भर्ती, समय पर ट्रेनिंग और अवस्थापना सुविधाओं के विकास से पुलिसकर्मियों के कार्य की गति बढ़ी है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर माहौल बना, और सुशासन का मॉडल खड़ा हुआ। सीएम योगी गुरुवार सुबह गोरखनाथ मंदिर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बने दो आधुनिक सुरक्षा भवनों के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इन भवनों में मंदिर सुरक्षा से जुड़े अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय, कंट्रोल रूम, पुलिस स्टोर रूम और मेंटिनेंस वर्कशाप बनाए गए हैं।

इसके निर्माण पर 9.18 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आई है। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा भवन का लोकार्पण करने के बाद भ्रमण और निरीक्षण कर भवन में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सुरक्षा, सुशासन की पहली शर्त होती है। हर व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए। इसके लिए सरकार के स्तर पर प्रयास किए जाते हैं। पर, हम उसका एक ही पक्ष देख पाते थे। पुलिस का सामान्य सिपाही हो या सब इंस्पेक्टर व डिप्टी एसपी, यदि उसकी ट्रेनिंग नहीं है तो वह भी एक कॉमन मैन (सामान्य व्यक्ति) ही होगा। सीएम योगी ने कहा कि पहले भर्ती, ट्रेनिंग और अवस्थापना सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता था। इसका परिणाम यह होता था कि बहुत से नौजवान पुलिस भर्ती में नहीं आना चाहते थे।

9 वर्ष में 2 लाख 19 हजार से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती

मुख्यमंत्री ने पुलिस महकमे में वर्ष 2017 के बाद आए बदलाव की चर्चा करते हुए कहा कि 9 साल पहले जब उनकी सरकार आई तो उस समय पुलिस बल में आधे से अधिक पद खाली थे। उन्होंने बताया कि बीते 9 वर्ष में 2 लाख 19 हजार से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया गया है। उन्होंने बताया कि 2017 के पुलिस की ट्रेनिंग क्षमता एक समय मे 3 हजार से अधिक नहीं थी। जबकि वर्तमान में अवस्थापना सुविधाओं के विकास का परिणाम है कि अब एक समय में 60 हजार पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग करवाई जाती है। समय पर लिए गए निर्णय, और समय पर दिए गए संसाधनों के परिणामस्वरूप पुलिस को 200 गुना सुविधाओं से सम्पन्न किया गया है।

पहले नहीं थी पुलिसकर्मियों के लिए अच्छी आवासीय सुविधा

सीएम योगी ने कहा कि पहले थाना हो, चौकी हो, पुलिस लाइन हो या पीएसी वाहिनी हो, कहीं पर पुलिसकर्मियों के लिए अच्छी आवासीय सुविधा और अच्छे बैरक नहीं थे। पुलिसकर्मी किराए पर रहकर जैसे–तैसे जीवन व्यतीत करता था। कई बार शिकायत आती थी कि पुलिस वाले ने घर पर कब्जा कर लिया है। वह कब्जा नहीं करता था। पता चलता था कि उसके बच्चे की परीक्षा है और मकान मालिक उससे घर खाली करने को कह देता। इस पर वह झल्ला कर कहता, घर नहीं खाली करेंगे। सीएम ने कहा कि यह सामान्य शिकायत आती थी। आज ये सारी शिकायतें समाप्त हो गई हैं क्योंकि सरकार ने हर पुलिस लाइन में आवासीय सुविधा दी है, बैरक बनवाए गए हैं।

सुरक्षा में सेंध लगाने वाले का काम तमाम कर देंगे मुस्तैद पुलिसकर्मी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले थाना का भवन बनता था लेकिन उसमें बैरक नहीं बनते थे। वहां अन्य सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पाती थीं। बहुत बार पुलिस किसी अपराधी को पकड़कर लाती थी तो रुकने की व्यवस्था नहीं होती थी। पुलिस कई बार असहाय दिखती थी। अपराधी भाग जाता था। सीएम ने कहा कि पुलिस को अब असहाय बनने की आवश्यकता नहीं है। अब अपराधी भाग नहीं सकता क्योंकि थाने में ही उसे रोके रखने की सुविधाएं दी गई हैं। उन्होंने कहा कि अब कोई थाने पर हमला नहीं कर सकता क्योंकि अब थाने में पुलिस कार्मिकों के लिए अलग से बेहतरीन सुविधाओं से युक्त बैरक बनाए गए हैं। हर समय, हर थाना में पर्याप्त संख्या में पुलिस कार्मिक उपलब्ध होंगे। जो थाने की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करेगा, उसके काम को तमाम करने के लिए पुलिसकर्मी वहां हमेशा मुस्तैद होकर के अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता हुआ दिखाई देगा। इस अवसर पर महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, एमएलसी एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, विधायक विपिन सिंह, महेंद्रपाल सिंह, प्रदीप शुक्ल, सरवन निषाद, प्रदेश सरकार के सलाहकार अवनीश अवस्थी, एडीजी गोरखपुर जोन मुथा अशोक जैन, एडीजी सुरक्षा तरुण गाबा, भाजपा के जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, महानगर संयोजक राजेश गुप्ता आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

नेटवर्क मार्केटिंग का जाल
दूसरों से बैंक में खुलवाते थे म्यूल खाते , खुद रखते थे ATM-PASSBOOK, सात गिरफ्तार

गोरखपुर,संवाददाता। छताछ में आरोपियों ने बताया कि ओमकार अग्रहरि उर्फ अजीत और ऋतुराज यादव के कहने पर वे लोगों को सरकारी योजनाओं के लाभ का लालच देकर जाल में फंसाते थे। जांच में आया है कि उन्होंने कई लोगों के खाते खुलवाए थे और उसके जरिये करोड़ों रुपये के ट्रांजेक्शन किए थे। सरकारी योजनाओं के लाभ का झांसा देकर म्यूल खाते खुलवाने और उसके जरिये साइबर ठगी की रकम ठिकाने लगाने वाले एक और गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। कोतवाली पुलिस ने बृहस्पतिवार को क्षेत्र से गिरोह के सात गुर्गों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने शुक्रवार को आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उन्नाव जिले के कोतवाली इलाके के सिविल लाइंस निवासी रवि सिंह उर्फ रामदास, चित्रकूट जिले के सरधुआ इलाके के सरधुआ निवासी ऋतुराज यादव, देवरिया जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के गरूलपार निवासी दिव्यांशु सिंह उर्फ साहिल सिंह, गोरखनाथ इलाके के हुमायूंपुर उत्तरी निवासी अनुज विश्वकर्मा उर्फ शुभम विश्वकर्मा, राजघाट थाना क्षेत्र के मिर्जापुर निवासी ओमकार अग्रहरि उर्फ अजीत, गगहा इलाके के कईधाखुर्द के राहुल सिंह, गोरखनाथ थाना क्षेत्र के हुमायूंपुर उत्तरी निवासी आदित्य चौधरी उर्फ सौरभ चौधरी के रूप में हुई।

दिव्यांशु वर्तमान में रामगढ़ताल इलाके के इंदिरानगर और रामदास लखनऊ के गुडंबा थाना क्षेत्र के कंचना बिहारी मार्ग कल्याणपुर में रहता था। पुलिस के अनुसार, लोगों को लालच देकर आरोपी उनके म्यूल खाते खुलवाते थे। उनके एटीएम कार्ड, पासबुक और चेक बुक अपने पास ही रखते थे। इसके बाद उनका इस्तेमाल साइबर फ्रॉड के रुपयों को ठिकाने लगाने के लिए करते थे। पुलिस के मुताबिक, कोतवाली थाने में एक तहरीर मिली जिसके बाद गिरोह का पता चला। पुलिस ने जांच कर पहले छह आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच के बाद एक और आरोपी को पकड़ा गया।

झांसा देकर खुलवाया बैंक खाता

पीड़ित विनोद कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि कुछ लोगों ने सरकारी योजनाओं के लाभ दिलाने के नाम पर उनके बेटे को अपने जाल में फंसाया और बैंक अकाउंट खुलवाया। फिर उसका पासबुक, एटीएम कार्ड और चेक बुक अपने पास रख लिया। कुछ समय बीत जाने के बाद भी जब व्यक्ति को कोई लाभ नहीं मिला तो उसे शक हुआ।

पता चला कि उसके खाते का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड के रुपयों को ठिकाने लगाने के लिए किया जा रहा है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की तो गिरोह के बारे में पता चला। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ओमकार अग्रहरि उर्फ अजीत और ऋतुराज यादव के कहने पर वे लोगों को सरकारी योजनाओं के लाभ का लालच देकर जाल में फंसाते थे। जांच में आया है कि उन्होंने कई लोगों के खाते खुलवाए थे और उसके जरिये करोड़ों रुपये के ट्रांजेक्शन किए थे। पीड़ित की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच में गिरोह का पता चला। सात गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य की तलाश जारी हैः निमिष पाटिल, एसपी सिटी

सड़क हादसे में गई जानः देर रात घर लौट रहे कंप्यूटर आपरेटर को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मौके पर ही हो गई मौत

सिद्धार्थनगर,संवाददाता। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।शुक्रवार देर रात घर लौट रहे इटवा विकास खंड में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर संदीप गुप्ता की सड़क हादसे में मौत हो गई। वह ड्यूटी खत्म कर अपने घर लौट रहे थे, तभी रगड़गज के पास किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया।

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जल्द ही आरोपी वाहन चालक को पकड़ने का दावा किया जा रहा है। परिजनों को हादसे की सूचना मिलते ही घर में कोहराम मच गया।

राप्ती नदी में नहाने गए चार दोस्त डूबने लगे- एक को लोगों ने बचाया
3 तेज बहाव में डूब गए, मौत

गोरखपुर,संवाददाता। बरियारपुर निवासी शुभम यादव (19), काजीपुर निवासी अभय उर्फ बंटी (18), शिव साहनी (20) और बुढ़ियाबारी निवासी शुभम यादव शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे राप्ती नदी में नहाने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि नहाते समय चारों अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। इसी दौरान बरियारपुर निवासी शुभम यादव किसी तरह तैरकर बाहर निकल आया और उसने शोर मचाकर लोगों को घटना की जानकारी दी। चिलुआताल क्षेत्र में बंजरहा स्थित राप्ती नदी घाट पर शुक्रवार दोपहर नहाने गए चार दोस्तों में से तीन गहरे पानी में डूब गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा–तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की टीम तलाश में जुटी रही। देर शाम तक उनका पता नहीं चल सका।

जानकारी के अनुसार, बरियारपुर निवासी शुभम यादव (19), काजीपुर निवासी अभय उर्फ बंटी (18), शिव साहनी (20) और बुढ़ियाबारी निवासी शुभम यादव शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे राप्ती नदी में नहाने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि नहाते समय चारों अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। इसी दौरान बरियारपुर निवासी शुभम यादव किसी तरह तैरकर बाहर निकल आया और उसने शोर मचाकर लोगों को घटना की जानकारी दी। स्थानीय लोगों ने तुरंत तीनों को बचाने की कोशिश की लेकिन तेज बहाव और गहराई अधिक होने के कारण सफलता नहीं मिल सकी। सूचना मिलते ही मजनू चौकी पुलिस और चिलुआताल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू कराई। बाद में एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान में जुट गई। इसी बीच एसएसपी डॉ. कौस्तुभ और एसपी उत्तरी ज्ञानेंद्र कुमार भी मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य का निरीक्षण किया। एसपी उत्तरी ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि चार युवक नहाने गए थे, जिनमें तीन डूब गए हैं जबकि एक सुरक्षित है। एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम लगातार तलाश कर रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार, राप्ती नदी के इस क्षेत्र में कई स्थानों पर अचानक गहराई बढ़ जाती है, जिसके कारण यहां अक्सर हादसे होते रहते हैं। घटना की जानकारी मिलते ही कैंपियरगंज विधायक फतेह बहादुर सिंह भी मौके पर पहुंचे। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुटे रहे। उधर, सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर प्रशासन ने घाट पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है।

पराली में लगी आग खेतों में फैली

अंबारी,संवाददाता। अहरौला थाना क्षेत्र के राजापुर माफी गांव में पराली में लग गई। इसमें किसान का भूसा जलकर राख हो गया। पीड़ित रामसूरत राम ने बताया कि माहुल और राजापुर माफी गांव के बीच चकमकसूदजहां की सीवान में स्थित खेतों में राजापुर माफी निवासी राम आसरे ने अपने गेहूं के कटे खेत की पराली में आग लगा दी। देखते ही देखते आग फैलकर आसपास के खेतों में पहुंच गई और कई किसानों की फसल अवशेष जलने लगे।

सूचना पाकर चौकी प्रभारी माहुल यश सिंह पटेल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। बाद में अग्निशमन दल को बुलाया गया।

तब तक आग की चपेट में आकर रामसूरत राम के खेत में रखा करीब 20 क्विंटल भूसा और लगभग 10 बीघा क्षेत्र की पराली जल चुकी थी। पीड़ित रामसूरत राम ने गांव के ही राम आसरे और उसके पुत्र के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। एसओ अहरौला अमित मिश्रा ने बताया कि मामले में जांच कर आरोपियों की तलाश की जा रही है, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।

ऑटो पार्ट्स की दुकान में आग, हजारों का नुकसान

बिलरियागंज। क्षेत्र के बघैला स्थित बाईपास मार्ग पर बृहस्पतिवार की भोर में एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में अचानक आग लग गई। घटना में दुकान में रखे मोटर पार्ट्स का सामान जल गया।

दुकान मालिक राजकुमार जायसवाल ने बताया कि आग लगने से करीब डेढ़ से दो लाख रुपये के सामान का नुकसान हुआ है, जबकि करीब 40 से 50 हजार रुपये नकद भी जल गए हैं। उन्होंने बताया कि सुबह करीब पांच बजे पड़ोसियों ने सूचना दी कि दुकान से धुआं निकल रहा है।

सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे ने बताया कि तहरीर मिली है। मामले की जांच कराई जा रही है।

पांच साल के रिश्ते का खौफनाक अंत

पार्टनर ने की प्रिंटिंग प्रेस संचालिका की हत्या, फिर शटर बंदकर किया ऐसा काम

गोरखपुर,संवाददाता। प्रिंटिंग प्रेस संचालिका गंगोत्री यादव की हत्या उसके पार्टनर अनिल गुप्ता ने की। चार लाख रुपये और शादी के विवाद में अनिल ने गंगोत्री का गला दबाकर मारा। पुलिस ने बृहस्पतिवार को अनिल को बस्ती से गिरफ्तार किया। कैंट इलाके के जिला पंचायत रोड स्थित प्रिंटिंग प्रेस संचालिका गंगोत्री यादव (25) की हत्या उसके ही पार्टनर अनिल गुप्ता ने गला दबाकर की थी।

पुलिस की जांच में पता चला कि गंगोत्री यादव ने जमीन खरीदने के लिए चार लाख रुपये जुटाए थे। इसकी जानकारी अनिल को भी थी। इस रकम को लेकर दोनों के बीच रविवार को विवाद हो गया और फिर गंगोत्री ने गुस्से में अनिल को थप्पड़ मार दिया था। इससे नाराज अनिल ने गंगोत्री को धक्का दे दिया और गिरने पर गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद आरोपी प्रिंटिंग प्रेस का शटर बंद कर भाग गया था।

पुलिस ने उसे बस्ती जिले के हरैया टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया। एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि मूलरूप से महराजगंज जिले के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के करमैनी गांव निवासी गंगोत्री यादव और कोतवाली के जगन्नाथपुर निवासी अनिल कुमार गुप्ता पिछले आठ वर्षों से साथ काम कर रहे थे और दोनों के बीच पांच साल से करीबी संबंध भी बन गए थे। गंगोत्री कर्ज लेकर दुकान चला रही थीं। धीरे–धीरे कर्ज चुकाने के साथ जमीन खरीदने के लिए रुपये जुटा रही थीं। इसी दौरान अनिल को रुपये के बारे में जानकारी हो गई और वह लगातार इन रुपयों को व्यापार में लगाने का दबाव बना रहा था, लेकिन गंगोत्री इसके लिए तैयार नहीं थी। रविवार को इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। गुस्से में आकर गंगोत्री ने अनिल को थप्पड़ मार दिया। इससे नाराज अनिल ने उसे धक्का दे दिया और गिरने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी पहले केबिन इसके बाद शटर बंद कर मौके से भाग गया। हत्या के बाद अनिल घर गया, कपड़े बदले और बिना किसी को बताए दिल्ली के लिए निकल गया। उधर, गंगोत्री के भाई रमेश यादव और उमाकांत उसकी तलाश में बुधवार को दुकान पहुंचे। बुधवार को दुकान से दुर्गंध आने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और जांच शुरू की।शुरुआती जांच में ही पुलिस का शक अनिल पर गया लेकिन उसका मोबाइल बंद मिला। लोकेशन के आधार पर पुलिस की एक टीम दिल्ली रवाना हुई, जबकि दूसरी टीम ने पीछा करते हुए बस्ती जिले के हरैया टोल प्लाजा के पास से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

शादी का दबाव बनाना भी एक वजह बनी

रुपयों के अलावा गंगोत्री और अनिल की दोस्ती भी गहरी हो गई थी। बताया जा रहा है कि गंगोत्री ने शादी करने पर भी चर्चा भी की थी, लेकिन अनिल ने पहले से शादीशुदा होने की बात कहते हुए टाल दिया था। पहले अनिल ने शादी की बात छिपाई थी। गंगोत्री को इसकी जानकारी होने पर दोनों के रिश्तों में खटास आ गई थी। गंगोत्री के परिजन उसकी शादी के लिए रिश्ता देख रहे थे।

पोस्टमार्टम के बाद परिजन महाराजगंज ले गए शव

बृहस्पतिवार को दो डॉक्टरों के पैनल ने वीडियोग्राफी के साथ गंगोत्री का पोस्टमार्टम किया। रिपोर्ट में सिर में चोट के साथ ही गला दबाने से मौत की पुष्टि हुई है। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया। इसके बाद परिजन शव लेकर गृह जनपद महाराजगंज रवाना हो गए।

महिला आरक्षण के मामले में गिरगिट की तरह रंग बदल रही कांग्रेस

सपा पर भी बरसी मायावती

लखनऊ,संवाददाता। बसपा सुप्रीमो मायावती ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर सपा–कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा व कांग्रेस ने सत्ता में रहने पर कभी भी एससी–एसटी और ओबीसी के हितों के लिए तय कोटे को कभी भी पूरा नहीं किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर कहा कि सत्ता में रहने पर कांग्रेस ने कभी भी एससी–एसटी और ओबीसी समाज के हितों का ध्यान नहीं रखा और अब इन वर्गों की महिलाओं की बात कर रही है। इसी तरह सपा का भी एससी–एसटी और ओबीसी के प्रति सत्ता में रहने पर तिरस्कारपूर्ण रवैया रहता है।

उन्होंने एक्स पर बयान जारी कर कहा कि

1. देश के अनुसूचित जाति–जनजाति व पिछड़े समाज के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के मामले में कांग्रेस गिरगिट की तरह अपना रंग बदलने पार्टी भी महिला आरक्षण में, जो अब इन वर्गों की बात कर रही है, वो यही कांग्रेस पार्टी है जिसने अपनी केन्द्र की सरकार के रहते हुये किसी भी क्षेत्र में इनके आरक्षण के कोटे को पूरा कराने की कभी पहल नहीं की।

2. तथा ना ही ओबीसी समाज हेतु मण्डल कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से उन्हें सरकारी नौकरी व शिक्षा के क्षेत्र में 27 प्रतिशत आरक्षण को भी लागू किया जिसे फिर बसपा के अथक प्रयासों से पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार में अनततः लागू किया गया था, जो सर्वविदित है।

3. इसी प्रकार, यूपी में पिछड़े मुस्लिमों को ओबीसी का लाभ देने के लिए, पिछड़ा वर्ग आयोग की जुलाई 1994 में ही आई रिपोर्ट को भी सपा सरकार ने ठण्डे बस्ते में डालकर इसे लागू नहीं किया था, जिसे फिर यहां बसपा की दिनांक 3 जून सन 1995 में पहली बनी सरकार ने इसे तुरन्त लागू किया। अब यही सपा अपना रंग बदलकर अपने राजनैतिक स्वार्थ में इनकी महिलाओं को अलग से आरक्षण देने की बात कर रही है।

4. इस प्रकार, अन्य मामलों की तरह इस मामले में भी सपा जब सरकार में नहीं है तो अलग रवैया अपना रही है, किन्तु जब सरकार में होती है तो अलग संकीर्ण जातिवादी व तिरस्कारी रवैया अपनाती है। अतः इन सभी वर्गों को ऐसी सभी छलावा एवं दोहरे चरित्र वाली पार्टियों से हमेशा सावधान रहना होगा तभी कुछ बेहतर संभव हो पाएगा।

5. जहां तक महिला आरक्षण के लिए पिछली (सन् 2011) जनगणना के आधार पर परिसीमन करने का सवाल है तो इस बारे में यही कहना है कि यदि इसे जिन भी कारणों से जल्दी लागू करना है तो फिर इसी जनगणना के आधार पर करना है और यदि वर्तमान में कांग्रेस पार्टी केन्द्र की सत्ता में होती तो फिर यह पार्टी भी बीजेपी की तरह ही यही कदम उठाती।

6. कुल मिलाकर, कहने का तात्पर्य यह है कि देश में एससी, एसटी व ओबीसी एवं मुस्लिम समाज के वास्तविक हित, कल्याण व उनके भविष्य संवारने आदि के किसी भी मामले में कोई भी पार्टी गम्भीर नहीं रही है।

7. इसीलिये महिला आरक्षण के मामले में इन वर्गों को अभी जो कुछ भी मिलने वाला है उसे इनको फिलहाल स्वीकार कर लेना चाहिये और इस मामले में आगे अच्छा वक्त आने पर इनके हितों का सही से पूरा ध्यान रखा जायेगा अर्थात इन्हें किसी के भी बहकावे में नहीं आना है क्योंकि इनको खुद अपने पैरों पर खड़े होकर अपने समाज को आत्मनिर्भर एवं मजबूत बनाना है। यही सलाह है।

निर्माण को मजबूत करेगी नैनो–सिलिका तकनीक

एएमयू वैज्ञानिकों को मिला पेटेंट नई तकनीक से ये होंगे फायदे

अलीगढ़,संवाददाता। यह तकनीक सीमेंट आधारित मिश्रण में नैनो–सिलिका के स्थिर वितरण के लिए एक सरल, किफायती और विस्तार योग्य विधि प्रदान करती है। बताते हैं कि इस तकनीक को बाजार में उतारने की तैयारी है। एएमयू के जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के वैज्ञानिकों को "ए नॉवेल नैनो सिलिका डिस्पर्स्ड सॉल्यूशन एंड ए प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन देअर ऑफ" तकनीक के लिए भारतीय पेटेंट मिला है। नैनो–सिलिका को व्हाइट कार्बन ब्लैक भी कहा जाता है, जो परमाणु स्तर पर सीमेंट की सामग्री के गुणों को बेहतर बनाने में मदद करता है। डॉ. साद शमीम अंसारी, डॉ. सैयद मोहम्मद इब्राहिम और प्रो. सैयद दानिश हसन ने यह तकनीक विकसित की है। यह तकनीक सीमेंट आधारित मिश्रण में नैनो–सिलिका के स्थिर वितरण के लिए एक सरल, किफायती और विस्तार योग्य विधि प्रदान करती है। बताते हैं कि इस तकनीक को बाजार में उतारने की तैयारी है। डॉ. साद शमीम अंसारी के अनुसार, नैनो–सिलिका तकनीक सिलिकॉन डाइऑक्साइड (एसआईओ–टू) के अति–सूक्ष्म कणों (1–100 एनएम) का उपयोग करने वाली एक नैनो–इंजीनियरिंग तकनीक है। यह अकार्बनिक पदार्थ अपनी उच्च सक्रियता के कारण सामग्री की मजबूती, टिकाऊपन और रासायनिक प्रतिरोध को बढ़ाता है। इसका मुख्य उपयोग कंक्रीट, रबर, कोटिंग्स और बायोमेडिकल क्षेत्रों में प्रदर्शन सुधारने के लिए किया जाता है।

अतीक व गुर्गों से खाली कराई गई जमीन पर शहरियों को मिलेंगे सस्ते घर

प्रयागराज,संवाददाता। अतीक अहमद और उसके गुर्गों के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर शहरियों को सस्ती दरों पर घर उपलब्ध कराए जाएंगे। भूमाफिया के अवैध कब्जे से खाली कराए जाने के बाद कुर्क की गई जमीन पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) आवासीय योजना विकसित करने की तैयारी कर रहा है। अतीक अहमद और उसके गुर्गों के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर शहरियों को सस्ती दरों पर घर उपलब्ध कराए जाएंगे। भूमाफिया के अवैध कब्जे से खाली कराए जाने के बाद कुर्क की गई जमीन पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) आवासीय योजना विकसित करने की तैयारी कर रहा है। पीडीए की ओर से शासन को पत्र भेजकर तहसील सदर के कटहुआ गौसपुर में 5.510 हेक्टेयर यानी 55,100 वर्ग मीटर जमीन निशुल्क उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया है। सूत्रों के अनुसार पीडीए की ओर से राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि न्यायालय पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट, प्रयागराज ने कटहुला गौसपुर में 5.510 हेक्टेयर भूमि को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी व क्रियाकलाप निवारण अधिनिय, 1986 के तहत कुर्क किए जाने का आदेश पारित किया था।

गैंगस्टर एक्ट के तहत राज्य में निहित हो गई हैं अतीक की संपत्तियां

इसी क्रम में प्रयागराज के विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अतीक अहमद व अन्य में 16 जुलाई 2024 को कुर्क संपत्तियों को राज्य में निहित कर दिया था। पत्र के जरिये कहा गया है कि विभिन्न जनपदों में भूमाफिया से खाली कराई गईं जमीनों को जनोपयोगी कार्यों में प्रयुक्त किया जाना है। पीडीए द्वारा भूमाफिया से खाली कराई गई जमीनों का नियमानुसार नियोजन एवं विकास कर आवासीय समस्याओं के निराकरण में सहयोग किया जा सकता है। पीडीए ने पत्र के साथ माफिया और कुर्क संपत्तियों की सूची भी प्रमुख सचिव को भेजी है और उनसे अनुरोध किया है कि भूमाफिया से रिक्त कराई गई एवं राज्य में निहित तकरीबन 5.510 हेक्टेयर जमीन जनोपयोगी कार्य के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण को निःशुल्क उपलब्ध करा दी जाए।

संभल में सरकारी जमीन पर बने इमामबाड़ा और ईदगाह पर चला बुलडोजर

संभल में सरकारी जमीन पर इमामबाड़ा-ईदगाह ध्वस्त। चार बुलडोजरों से 14.75 बीघा अवैध कब्जा हटाया। विरोध के बावजूद भारी पुलिस बल की तैनाती में कार्रवाई।

संवाददाता, संभल। कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव बिछौली में सरकारी खाद के गड्ढों व पशुचर की भूमि पर अवैध निर्माण करके ईदगाह व इमामबाड़ा बना लिया गया था। कीब तीन माह पहले पैमाइश के बाद नोटिस जारी किए गए, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में तहसीलदार न्यायालय की ओर से बेदखली के आदेश दे दिए गए थे। राजस्व विभाग की टीम भारी पुलिस बल व पीएसी जवानों के साथ गांव में पहुंची। जहां चार बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण को ध्वस्त करने का काम शुरू कर दिया गया।

क्षेत्र के चंदौसी मार्ग स्थित गांव बिछौली में गुरुवार की सुबह को एसडीएम निधि पटेल के निर्देशन व नायब तहसीलदार दीपक जुरैल के नेतृत्व में दो राजस्व निरीक्षक व सात लेखपालों की टीम पहुंची। टीम द्वारा पूर्व में गाटा संख्या 1240 के खाद के गड्ढे की रकबा 0.166 हेक्टेयर (करीब ढाई बीघा) बने इमामबाडा तथा गाटा संख्या 1242 के पशुचर की रकबा 0.766 हेक्टेयर (करीब सवा 12 बीघा) भूमि पर बने ईदगाह को चिह्नित किया।

मौके पर लोगों ने किया विरोध

उसके बाद मौके पर मौजूद चार बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का कार्य शुरू कर दिया गया। इमामबाडा और ईदगाह के निर्माण ध्वस्त किए जाने की जानकारी के बाद काफी संख्या में ग्रामीणों की मौके पर भीड़ लग गई। ऐसे में मौके पर मौजूद पुलिस व पीएसी जवानों ने भीड़ को मौके से खदेड़ दिया। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पांच थानों की पुलिस के साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल और एक कंपनी पीएसी व आरआरएफ को तैनात किया गया था।

इस बीच डीएम एसपी ने भी मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का जायजा लिया।

एसडीएम निधि पटेल ने बताया कि सरकारी आरक्षित दो गाटा संख्या की भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण कर लिया गया था। तहसीलदार न्यायालय की ओर से इस मामले में बेदखली के आदेश दिए गए थे। जिसका आज राजस्व विभाग की टीम द्वारा पुलिस बल की मौजूदगी में अनुपालन कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब सुबह टीम गांव में पहुंची तो इमामबाड़ा की रेलिंग को गांव के लोग स्वयं ही तोड़ रहे थे।

500 झुग्गियों में लगी भीषण आग

एक-एक कर फट रहे सिलिंडर धमाकों से दहल उठे लोग

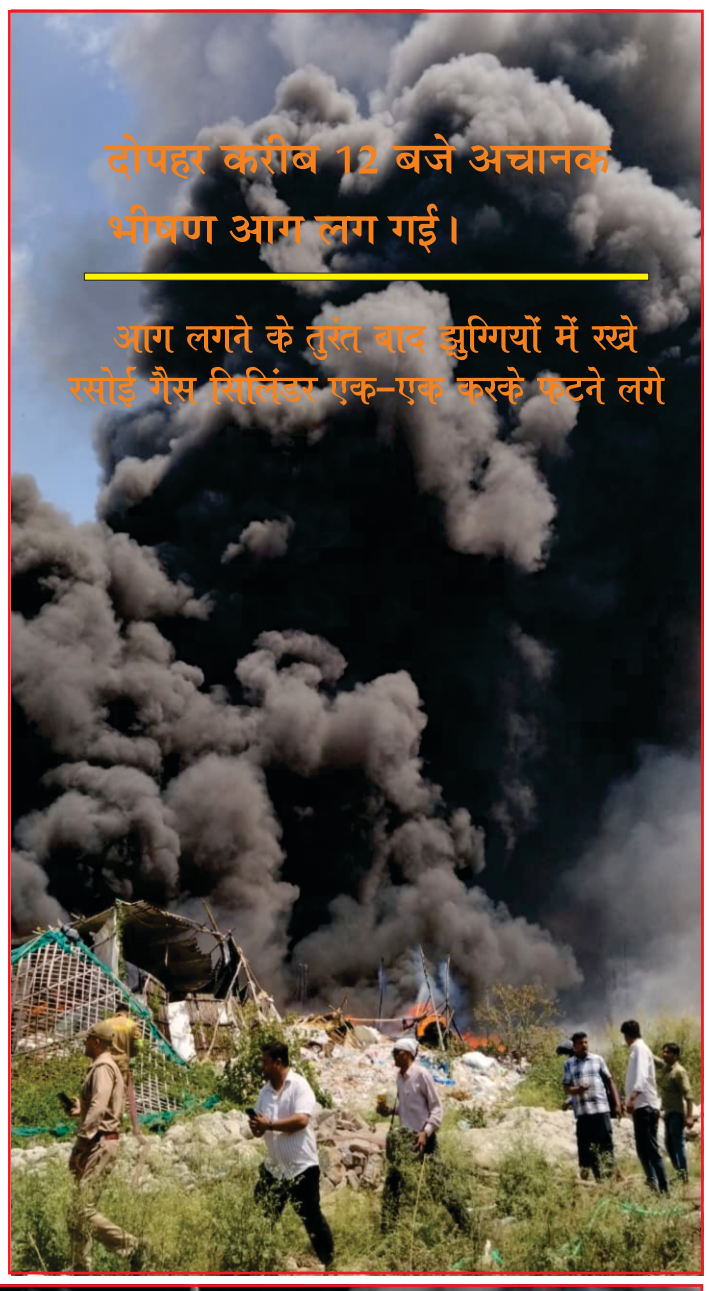

गाजियाबाद,संवाददाता। कनवानी गांव में झुग्गियों में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने 500 से ज्यादा झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान झुग्गियों में रखे सिलिंडर एक-एक कर कर फटने लगे। धमाकों से इलाके के लोग दहल उठे।गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के कनवानी गांव में बृहस्पतिवार दोपहर करीब 12 बजे अचानक भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में 500 से अधिक झुग्गियां देखते ही देखते जलकर राख हो गईं। आग की लपटें इतनी विकराल थीं कि दूर से ही दिखाई दे रही थीं, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

आग लगने के तुरंत बाद झुग्गियों में रखे रसोई गैस सिलिंडर एक-एक करके फटने लगे। इन धमाकों की आवाज से पूरा क्षेत्र दहल उठा और लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस बल और दमकल विभाग की कई टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने बिना देरी किए आग बुझाने का काम शुरू कर दिया।

आग पर काबू पाने के लिए दर्जनों दमकल गाड़ियां लगाई गई हैं। अग्निशमन अभियान में कई घंटे लगने की संभावना है क्योंकि आग बड़े क्षेत्र में फैली है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस और दमकल की टीमों ने युद्धस्तर पर बचाव कार्य शुरू किया। आग बुझाने के लिए लगातार पानी की बौछारें की जा रही हैं। स्थानीय निवासियों ने भी अपनी जान जोखिम में डालकर आग बुझाने में मदद की कोशिश की। इस भीषण अग्निकांड से सैकड़ों परिवारों का आशियाना उजड़ गया है। उनके पास खाने-पीने और रहने का कोई साधन नहीं बचा है। आग से हुए भारी नुकसान का आकलन किया जाएगा। पुलिस ने आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है।

तिलक समारोह में खाना खाने से 40 लोगों को फूड पाइजनिंग

रायबरेली,संवाददाता। रायबरेली में तिलक समारोह में खाना खाने से 40 लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद सभी को राहत मिली। यूपी के रायबरेली में तिलक समारोह में खाना खाने के कुछ देर बाद 40 लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई। उन्हें आनन फानन सीएचसी पहुंचाया गया। वहां इलाज के बाज उनकी हालत में सुधार आया। मामला शिवगढ़ कस्बा का है। यहां के रहने वाले राजन गुप्ता के बेटे सुशील गुप्ता का बुधवार को तिलक था। इसमें क्षेत्र के सैकड़ों लोग आमंत्रित थे। कार्यक्रम बछरावा स्थित एक मैरिज हाल में था। मैरिज हाल में आयोजित भोज में सब लोगों ने खाना खाया। आधी रात करीब 12.30 बजे कई लोगों की हालत बिगड़ने लगी। उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, शिवगढ़ पहुंचाया गया। वहां इमरजेंसी में तैनात डॉ अनिल और प्रमोद पांडेय ने 40 लोगों का इलाज किया ।

बीमार लोगों में सुमन (30), आदर्श (17) प्रेमा (65) शकीला (46) कुसुम लता (65) ज्ञानेंद्र (35) अजय जायसवाल (36) वर्षा (10) प्रदीप सिंह (32) कुदरत अली (48) मुराद (18) सोनू (50) अंकुश (15) सानवी (6) सचिन (15) साधना (29) दुर्गेश (37) आदि 40 लोग शामिल हैं। डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि बताया कि फूड पॉइजनिंग से उल्टियां हो रही थीं। दवा देकर घर भेज दिया गया है। सभी की हालत खतरे से बाहर है। किसी को रेफर नहीं किया गया है।

'करना चाहती हूं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी'

बेटी की इस मांग पर पिता ने कहा गलत राह पर हो; कोर्ट पहुंची

प्रयागराज,संवाददाता। मुरादाबाद की एक युवती ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाते हुए कहा है कि मैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहती हूं। पिता ने इस मांग को खारिज कर दिया। इस पर युवती ने कोर्ट में गुहार लगाई। अब कोर्ट ने मुरादाबाद के एसएसपी को जांच का आदेश दिए गए हैं। सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट तलब की है। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में परिवार को बाधक बताकर मुरादाबाद की युवती ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं, पिता ने बेटी की गुमशुदगी दर्ज करा साथ रहने वाली सहेली पर उसे बहलाकर गलत काम में धकेलने का आरोप लगाया है। मामला छजलैट थाना क्षेत्र का है। पिता ने बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई। उधर बेटी, उसके साथ रह रही सहेली ने पिता और अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ याचिका दाखिल कर कोर्ट से सुरक्षा की मांग की है।

'सहेली संग रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की करना चाहती हूं तैयारी'

याची युवती का दावा है कि वह बालिग है। मुरादाबाद के पीतल नगरी में अपनी सहेली संग रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहती है। उसकी सहेली उसे आर्थिक सहायता मुहैया करा रही है। जबकि, उसके पिता और अन्य रिश्तेदार इसका विरोध कर रहे है। वह पढ़ाई छुडवा कर उसे घर ले जाना चाहते हैं।

याची के अधिवक्ता ठाकुर प्रसाद दुबे ने दलील दी कि बालिग बेटी को पढ़ाई करने, अपनी मर्जी से नौकरी की तैयारी करने से रोकना स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है।

'बेटी सहेली के बहकावे में है'

वहीं, दूसरी तरफ पिता के अधिवक्ता राजेश कुमार यादव ने सनसनीखेज दावा किया। कहा कि बेटी सहेली के बहकावे में है। एक अप्रैल से गायब है। इसकी गुमशुदगी की एनसीआर थाने में दर्ज कराई गई है। पिता का आरोप है कि उसकी सहेली बेटी को गुमराह कर गलत कामों में धकेलने की कोशिश कर रही है। मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए कोर्ट ने एसएसपी मुरादाबाद जांच का आदेश दिया है। कहा है कि मामले की जांच पुलिस उपाधीक्षक रैंक के अधिकारी से कराई जाए।

हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ही यह पारित हो जाए, मैं सबका आभार प्रकट करने के लिए तैयार हूं। जिसकी फोटो आप कहेंगे, सरकारी खर्चे से उसकी फोटो छपवा देंगे। क्रेडिट का ब्लैंक चेक दे रहा हूं।

पीएम मोदी, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर

'हम महिला आरक्षण के साथ हैं, लेकिन भाजपाई चालबाजी के खिलाफ हैं : अखिलेश यादव

BJP-RSS का माइक्रो मैनेजमेंट क्या बंगाल में बदलेगा गेम

BJP-RSS की 12 रणनीतियां, जो बंगाल में बदलेंगी समीकरण

1. किसान, व्यापारी और मजदूरों पर फोकस
2. 1 बूथ-10 यूथ स्ट्रैटजी
3. YM यानी युवा और महिलाएं
4. दलबदलुओं को तवज्जो नहीं
5. मुस्लिमों को टिकट नहीं
6. सुबह-सुबह वोट डलवाने की रणनीति
7. नॉर्थ बंगाल में मजबूती पर फोकस
8. NOTA न दबाने की अपील
9. बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का फैक्टर
10. हर बूथ पर क्विक रिस्पॉन्स टीम
11. मतुआ, राजवंशी और बांग्लादेशी शरणार्थियों को साधना
12. 5 पत्तों की इकोनॉमी वाले आदिवासियों को साथ लाना

पश्चिम बंगाल में बूथ से लेकर बॉर्डर तक BJP और RSS एक्टिव हैं।

BJP ने सीनियर लीडर रहीं सुषमा स्वराज का फॉर्मूला '1 बूथ-10 यूथ' पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों पर लागू किया है।

लागू हुआ 2023 का महिला आरक्षण कानून

संविधान संशोधन पर चर्चा के बीच ही अधिसूचना जारी

नई दिल्ली,एजेंसी। संसद का विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा चल रही है। अभी चर्चा के लिए कल का भी दिन बचा है, लेकिन सरकार ने गुरुवार को ही नोटिफिकेशन जारी महिला आरक्षण कानून को लागू कर दिया है। महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 गुरुवार से लागू हो गया है। केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह कानून 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गया है हालांकि, यह साफ नहीं है कि जब संसद में इस कानून पर चर्चा चल ही रही है तो फिर इसे आज से ही लागू क्यों किया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 1(2) के तहत केंद्र सरकार ने 16 अप्रैल 2026 को इस कानून के लागू होने की तिथि निर्धारित की है।

सितंबर 2023 में संसद ने दी थी मंजूरी

सितंबर 2023 में संसद ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पारित किया था, जिसे महिला आरक्षण कानून के नाम से जाना जाता है। इसे विधायिकाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना गया था। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है।

2029 तक नहीं मिल सकेगा आरक्षण का फायदा

हालांकि, 2023 के इस कानून के अनुसार आरक्षण का फायदा 2029 से पहले नहीं मिल सकेगा, क्योंकि इसे 2027 की जनगणना के बाद होने वाली परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ा गया है।

वर्तमान में लोकसभा में जिन तीन विधेयकों पर चर्चा चल रही है, उनका उद्देश्य महिला आरक्षण को 2029 से लागू करना है। अधिकारियों के मुताबिक, कानून लागू हो जाने के बावजूद मौजूदा लोकसभा में यह आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए अगली जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है।

संसद में इन संशोधन विधेयकों पर चर्चा जारी

संसद के विशेष सत्र में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026, परिसीमन संशोधन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा चल रही है। इन विधेयकों में लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। परिसीमन विधेयक के तहत जनसंख्या की परिभाषा में बदलाव किया जाएगा ताकि 2011 की जनगणना को आधार बनाया जा सके।

महिला आरक्षण विधेयक से जुड़े संशोधनों पर चर्चा के दौरान गुरुवार को पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा कि परिसीमन में किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह मोदी की गारंटी है और वादा है। पीएम मोदी ने कहा, 'हम भ्रम में न रहें, हम अहंकार में न रहें। यहां मैं और तुम की बात नहीं कर रहा हूं। हम हम देश की नारी शक्ति को कुछ दे रहे हैं। ये उनका हक है। और हमने कई दशकों से उनको रोका है। आज उसका प्रायश्चित करके उस अपराध से मुक्ति पाने का अवसर है।'गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि 3 बिलों से दक्षिण के राज्यों की लोकसभा सीटें कम हो जाएंगी। उन्होंने कहा, 'लोकसभा की कुल 543 सीटों में दक्षिण राज्यों की 129 सीटें हैं। परिसीमन के बाद यह बढ़कर 195 हो जाएंगी। तमिलनाडु की सीटें 39 से बढ़कर 59 होंगी।'

कौन है सय्यद दाउद, जो कनाडा से चला रहा है धर्मांतरण का गिरोह

आगरा,संवाददाता। धर्मांतरण गैंग में विदेशी फंडिंग करने वाले आरोपी पर एक और एफआईआर दर्ज की गई है, जो कनाडा में छिपा बताया जा रहा है। पुलिस जांच में पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने के बाद अब उसकी संपत्ति कुर्क करने की तैयारी की जा रही है।

धर्मांतरण गैंग में विदेशी फंडिंग का काम करने वाले भोपाल के निवासी सय्यद दाउद पर सदर थाने में एक और प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसके घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा होने के बाद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई है। विवेचक साइबर थाना प्रभारी रीता सिंह ने उसके खिलाफ तहरीर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी कनाडा में छिपा हुआ है। सदर क्षेत्र की दो सगी बहनों की गुमशुदगी थाना सदर में दर्ज हुई थी। जांच में उनका धर्म परिवर्तन करवाकर धर्मांतरण के गैंग में शामिल किए जाने का पता चला था। पुलिस टीम ने धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश करते हुए 6 राज्यों से गैंग के 13 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। दोनों बहनों को मुक्त करवाकर परिजन के सुपुर्द किया था। आरोपियों को न्यायालय ने जेल भेजा था।

बंगाल जीतने की जिम्मेदारी इन नेताओं को

यूपी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार और भाजपा संगठन में नियुक्तियां इसी हफ्ते

लखनऊ,संवाददाता। दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने इन मुद्दों पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन व राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष के साथ लंबी बैठक की। बंद कमरे में बैठक के बाद माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में बदलाव के स्वरूप को इसी हफ्ते अंतिम रूप दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार और भाजपा प्रदेश संगठन में पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर प्रदेश के बाद अब दिल्ली में मंथन शुरू हो गया है। बृहस्पतिवार को दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने इन मुद्दों पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन व राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष के साथ लंबी बैठक की।

बंद कमरे में बैठक के बाद माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में बदलाव के स्वरूप को इसी हफ्ते अंतिम रूप दिया जाएगा। वहीं, पार्टी सूत्रों के मुताबिक दोनों स्तरों पर बदलाव के लिहाज से अगले सप्ताह के शुरुआती दो-तीन दिन अहम हैं। सूत्रों का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार होने की पूरी संभावना है। इसके बाद संगठन के नये पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी जाएगी। बता दें कि यूपी में संगठन चुनाव के प्रेक्षक विनोद तावड़े ने हाल ही में दो दिनों तक लखनऊ में प्रवास किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री, दोनों उपमुख्यमंत्री, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर दोनों मुद्दों के अलावा निगमों और बोर्डों में मनोनयन पर रायशुमारी की। विनोद तावड़े ने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट सौंप दी थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर आखिरी फैसला लेने के लिए अंतिम दौर की बैठक हो रही है। सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार या शनिवार को सभी पदाधिकारियों की मुलाकात अमित शाह से होगी। इसके बाद फैसला लिया जाएगा।

वरुण धवन की भतीजी से मिलिए

वरुण धवन की भतीजी अंजिनी ने बहुत कम उम्र में ही ग्लैमरस वर्ल्ड में कदम रख दिया. उनका जन्म 4 अप्रैल 2000 में हुआ था. अब वो 26 साल की हैं. फिल्मों में एक्टिंग से पहले कुली नंबर 1 में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम भी कर चुकी हैं।

आदित्य धर ने 'धुरंधर' के स्टंटमैन को लेकर किया ये खुलासा

मुम्बई,एजेंसी। धुरंधर' को फैंस ने भर–भरकर प्यार दिया. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने कई रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए. फिल्म को आदित्य धर ने बनाया है. आदित्य धर अब फिल्म की टीम के लिए पोस्ट कर रहे हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं. अब आदित्य ने एक्शन टीम के लिए पोस्ट किया और बताया कि कैसे फिल्म के खतरनाक सीन्स को शूट किया गया.

आदित्य धर की पोस्ट

आदित्य धर ने एक्शन टीम के लिए पोस्ट लिखा. उन्होंने लिखा, 'धुरंधर की मेरी एक्शन टीम के लिए– एजाज गुलाब, सी यंग ओह, यानिक बेन, रमजान बुलुत और विशाल त्यागी. कन्विक्शन और पागलपन के बीच एक बहुत पतली लकीर होती है. इस फिल्म में मैंने लगभग हर दिन उस लाइन को पार किया है. मैं एजाज भाई के पास ऐसे–ऐसे आइडिया लेकर जाता था, जो मुझे पता होता था कि वो बेतुके लगते हैं. जैसे किसी आदमी को एक बड़े से इंडस्ट्रियल प्रेशर कुकर के अंदर डालना, किसी को बिजी सड़क पर बाइक के पीछे गले में फंदा डालकर घसीटना. या तीस आदमियों को पंखों से उल्टा लटकाकर और घुमा देना. ये सिर्फ आइडिया नहीं थे ये बल्कि ऐसी परेशानी थी जिन्हें मैं उनको सौंप देता था.'

'काकटेल 2' के लिए कृति सेनन ने कैसे घटाया अपना वजन

एंटरटेनमेंट डेस्क। कृति सेनन जल्द ही 'कॉकटेल 2' में नजर आने वाली हैं। मूवी के फर्स्ट लुक में एक्ट्रेस काफी फिट और बोल्ड लुक में नजर आईं हैं। हाल ही में उन्होंने इसके लिए ली गई डाइट और रूटीन पर चर्चा की। जानिए उन्होंने क्या कहा।शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना जल्द ही अपनी आने वाली फिल्म 'कॉकटेल 2' में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म 2012 में आई 'कॉकटेल' का सीक्वल है।

'कॉकटेल 2' के क्लिप्स में कृति काफी फिट और बोल्ड नजर आ रही हैं। अब उन्होंने इसी को लेकर अपनी डाइट और रूटीन को लेकर खुलकर बात की। जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा।

मैं स्ट्रिक्ट डाइट और कंसिस्टेंट वर्कआउट रूटीन पर थी

आईएएनएस से बातचीत में कृति सेनन ने कहा, 'सच कहूं तो 'कॉकटेल' के दौरान ही ऐसा हुआ था जब मैं बहुत स्ट्रिक्ट डाइट और कंसिस्टेंट वर्कआउट रूटीन पर थी और पहली बार मैंने कैलोरी–डेफिसिट डाइट फॉलो की, जो मैंने पहले कभी अपनी जिंदगी में नहीं किया था। हम इटली के सिसिली में शूट कर रहे थे और वहां खाने की बात करें तो ज्यादातर पिज्जा, पास्ता, पिज्जा वही सब होता है। और मैं बस सोचती रह जाती थी।'

क्या होती है कैलोरी–डेफिसिट डाइट?

कैलोरी–डेफिसिट डाइट का मतलब शरीर की नॉर्मल कैलोरी मात्रा से कम कैलोरी लेना। इसका मोटिव वजन घटाने के लिए शरीर में जमा फैट को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करने पर मजबूर करना होता है। इसमें आमतौर पर रोज के खाने में 500–1000 कैलोरी कम की जाती है, जिससे हर सप्ताह लगभग 1 किलो वजन कम हो सकता है।

सारा अर्जुन को मिल सकता है मौका

सारा अर्जुन को मिली साउथ की फिल्म

सारा अर्जुन का काम

इस समय सारा अर्जुन अपनी फिल्म 'धुरंधर 2' की सफलता का आनंद ले रही हैं। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया है। 27 दिनों में इसने 1095.67 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट 'धुरंधर' ने भी अच्छी कमाई की थी। इसमें भी सारा अर्जुन थीं।

एंटरटेनमेंट डेस्क। 'धुरंधर' से मशहूर हुईं अभिनेत्री सारा अर्जुन जल्द ही साउथ की एक फिल्म में नजर आ सकती हैं। खबरें हैं कि पहले इस फिल्म में रुक्मिणी वसंत को लिया जाना था लेकिन अब सारा के नाम पर विचार किया जा रहा है। सारा अर्जुन आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' में अपनी अदाकारी की वजह से चर्चा में हैं। वह इस समय सबसे ज्यादा मशहूर अभिनेत्रियों में से एक हैं। इस बीच, एक रिपोर्ट सामने आई है कि यह स्टार, नेशनल अवॉर्ड विजेता अभिनेता धनुष के साथ एक अपकमिंग फिल्म में नजर आ सकती हैं। इस फिल्म के निर्देशक तमिलरासन पचामुथु होंगे।

123 तेलुगु के मुताबिक धनुष के पास निर्देशक तमिलरासन पचामुथु के साथ एक प्रोजेक्ट है। इस फिल्म में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर रुक्मिणी वसंत को चुना गया था। मगर अब ऐसा लगता है कि अब वह इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हैं। वह एनटीआर और प्रशांत नील की फिल्म में बिजी हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म के मेकर्स अब मुख्य अभिनेत्री के तौर पर सारा अर्जुन के नाम पर विचार कर रहे हैं। हालांकि, अभी तक इस बारे में कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

स्टार्स फेल...प्लान फ्लाप!: क्यों नहीं जीत पा रही हार्दिक की मुंबई इंडियंस? टीम की लगातार नाकामी के पांच कारण

स्पोर्ट्स डेस्क। मुंबई इंडियंस का आईपीएल 2026 अभियान खराब फॉर्म, कमजोर गेंदबाजी और स्टार खिलाड़ियों के फ्लॉप प्रदर्शन के कारण पटरी से उतर गया है। सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह जैसे बड़े नाम उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं, जबकि स्पिन और डेथ बॉलिंग भी कमजोर रही है।

इन पांच कारणों के चलते मुंबई इंडियंस की टीम लगातार हार झेल रही है और टीम को जल्द सुधार की जरूरत है। मुंबई इंडियंस का आईपीएल 2026 सीजन अब तक उम्मीदों के बिल्कुल उलट रहा है। टीम ने पांच मैचों में से चार में हार झेली है और अंक तालिका में नीचे की ओर फिसलती जा रही है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम से बड़े प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन नतीजे इसके उलट दिखे हैं। दिलचस्प बात यह है कि टीम में कई मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं, फिर भी जीत दूर नजर आ रही है। आइए विस्तार से समझते हैं वो पांच बड़े कारण, जिनकी वजह से मुंबई इंडियंस का यह बुरा हाल है–

1. मिडिल ऑर्डर की रीढ़ टूटना

सूर्यकुमार यादव की खराब फॉर्म मुंबई इंडियंस के लिए सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। मिडिल ऑर्डर के इस भरोसेमंद बल्लेबाज ने इस सीजन पांच मैचों में सिर्फ 106 रन बनाए हैं, जो उनके कद और क्षमता के हिसाब से काफी कम है। खास बात यह है कि पिछले सीजन उन्होंने 16 मुकाबलों में 717 रन ठोककर टीम को दूसरे क्वालिफायर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन इस बार उनका बल्ला पूरी तरह खामोश नजर आ रहा है। सूर्यकुमार आमतौर पर ऐसे खिलाड़ी हैं जो मुश्किल हालात में पारी को संभालते हुए तेजी से रन गति भी बढ़ाते हैं, लेकिन उनकी नाकामी का सीधा असर टीम की बल्लेबाजी पर पड़ा है। नतीजतन, मुंबई इंडियंस बीच के ओवरों में रन बनाने की रफ्तार बनाए रखने में संघर्ष कर रही है और यही वजह है कि टीम बार–बार दबाव में आकर मुकाबले गंवा रही है।

2. कप्तान हार्दिक पांड्या का फीका प्रदर्शन

हार्दिक पांड्या से इस सीजन मुंबई इंडियंस को एक मजबूत ऑलराउंड प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन अब तक वह उस स्तर पर खरे नहीं उतर पाए हैं। उन्होंने शुरुआती मैचों में बल्ले से सिर्फ 81 रन बनाए हैं और उनका औसत भी महज 27 का रहा है, जो एक फिनिशर के तौर पर उनकी भूमिका के मुताबिक पर्याप्त नहीं माना जा सकता। गेंदबाजी में जरूर उन्होंने सात विकेट हासिल किए हैं, लेकिन 9.17 की ऊंची इकोनॉमी यह दिखाती है कि वह रन रोकने में प्रभावी नहीं रहे। आमतौर पर हार्दिक उन खिलाड़ियों में गिने जाते हैं जो दबाव के क्षणों में मैच को अंत तक ले जाकर जीत दिलाते हैं, लेकिन इस बार वह उस भरोसे पर खरे नहीं उतर सके हैं। उनकी इस फीकी फॉर्म का सीधा असर टीम के नतीजों पर पड़ा है, क्योंकि मुश्किल हालात में मुंबई इंडियंस को कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं मिल पा रहा जो मैच को संभालकर जीत तक पहुंचा सके।

3. तिलक वर्मा का संघर्ष

तिलक वर्मा मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजी क्रम में संतुलन बनाने वाले अहम खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन इस सीजन उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। उन्होंने पांच मैचों में सिर्फ 43 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 134 का रहा है, जो टी20 के लिहाज से खास प्रभावी नहीं माना जाता। तिलक से यह अपेक्षा रहती है कि वह मिडिल ऑर्डर में पारी को स्थिरता दें और जरूरत पड़ने पर रन गति भी बढ़ाएं, लेकिन लगातार नाकामी के चलते वह अपनी भूमिका निभाने में सफल नहीं हो पाए हैं। उनकी खराब फॉर्म का असर पूरी टीम की बल्लेबाजी पर साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब मिडिल ऑर्डर का भरोसेमंद खिलाड़ी ही रन नहीं बना पाता, तो पूरी लाइनअप दबाव में आ जाती है और यही वजह है कि मुंबई इंडियंस का बल्लेबाजी क्रम इस सीजन पूरी तरह अस्थिर नजर आ रहा है।

4. जसप्रीत बुमराह का विकेट न लेना

जसप्रीत बुमराह जैसे वर्ल्ड क्लास गेंदबाज का पांच मैचों में एक भी विकेट न ले पाना इस सीजन मुंबई इंडियंस के लिए सबसे चौंकाने वाली बातों में से एक रहा है।

बुमराह आमतौर पर डेथ ओवर्स में अपनी सटीक गेंदबाजी और यॉर्कर के दम पर विपक्षी टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोकते हैं, लेकिन इस बार वह उस प्रभाव को नहीं छोड़ पाए हैं। उनके विकेट न निकाल पाने के कारण विरोधी बल्लेबाजों पर दबाव नहीं बन पा रहा और टीमें आसानी से बड़े स्कोर खड़े कर रही हैं। इसके अलावा ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर और शार्दुल ठाकुर जैसे अनुभवी गेंदबाज भी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे पूरी गेंदबाजी इकाई कमजोर नजर आ रही है। कुल मिलाकर, विकेट लेने की कमी और रन रोकने में नाकामी ने मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी को पूरी तरह बेअसर बना दिया है।

5. स्पिन अटैक की कमजोरी

मुंबई इंडियंस के लिए इस सीजन सबसे बड़ी परेशानी उनका कमजोर स्पिन अटैक साबित हुआ है। मिडिल ओवर्स में जहां आमतौर पर स्पिनर खेल का रुख बदलते हैं, वहीं इस बार टीम को वहां से न तो विकेट मिल पा रहे हैं और न ही रन पर लगाम लग रही है। अल्लाह गजनफर काफी महंगे साबित हुए हैं और उनका इकोनॉमी रेट 10.71 तक पहुंच गया है, जो टी20 क्रिकेट में किसी भी टीम के लिए चिंता का विषय होता है। दूसरी ओर मिचेल सैंटनर भी विकेट निकालने में प्रभावी नहीं रहे हैं, जिससे विपक्षी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका मिल रहा है। नतीजतन, मुंबई इंडियंस मिडिल ओवर्स में मैच पर पकड़ बनाने में असफल रही है और यही कमजोरी कई मुकाबलों में टीम की हार की बड़ी वजह बन गई है।

समस्या सिर्फ एक नहीं, पूरी टीम का संतुलन बिगड़ा

मुंबई इंडियंस की मौजूदा स्थिति यह साफ दिखाती है कि परेशानी किसी एक खिलाड़ी या किसी एक विभाग तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी टीम का संतुलन ही बिगड़ गया है। बल्लेबाजी में निरंतरता की कमी लगातार देखने को मिल रही है, जहां कोई भी खिलाड़ी लंबे समय तक जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा। वहीं गेंदबाजी में वह धार नजर नहीं आ रही, जो कभी इस टीम की सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी। सबसे अहम बात यह है कि कप्तान और बड़े स्टार खिलाड़ी भी फॉर्म में नहीं हैं, जिससे टीम का आत्मविश्वास प्रभावित हो रहा है। ऐसे में जब तक ये सभी समस्याएं एक साथ दूर नहीं होतीं और टीम एक यूनिट के तौर पर बेहतर प्रदर्शन नहीं करती, तब तक मुंबई इंडियंस के लिए इस सीजन में वापसी करना काफी मुश्किल नजर आता है।

चोटिल डेविड पेन की जगह सनराइजर्स की टीम में आया यह तूफानी गेंदबाज

स्पोर्ट्स डेस्क। सनराइजर्स हैदराबाद ने चोटिल डेविड पेन की जगह दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज गेराल्ड कोएत्जी को आईपीएल 2026 के बाकी सीजन के लिए टीम में शामिल किया है। पेन टखने की चोट के कारण बाहर हो गए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2026 के बीच बड़ा फैसला लेते हुए दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज गेराल्ड कोएत्जी को इंग्लैंड के डेविड पेन की जगह टीम में शामिल किया है। डेविड पेन टखने की चोट के कारण पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं। उन्होंने इस सीजन में एसआरएच के लिए दो मैच खेले थे और दो विकेट लिए थे।

दो करोड़ रुपये में फ्रेंचाइजी से जुड़े कोएत्जी

फ्रेंचाइजी ने कोएत्जी को दो करोड़ रुपये में टीम में जोड़ा है। कोएत्जी के पास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छा अनुभव है, उन्होंने अब तक चार टेस्ट, 14 वनडे और 18 टी20 मुकाबलों में कुल 67 विकेट लिए हैं। आईपीएल में अनुभव की बात करें तो वह पहले मुंबई इंडियंस (2024) और फिर गुजरात टाइटंस (2025) की टीम का हिस्सा रह चुके हैं। आईपीएल में उन्होंने 14 मैचों में 15 विकेट लिए हैं।

सत्र की पहली जीत को तरसी केकेआर

अब गुजरात से भी हारी मुकाबला; गिल का लगातार तीसरा 50+ स्कोर

स्पोर्ट्स डेस्क। गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को पांच विकेट से हरा दिया। शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर ने 20 ओवर में 10 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में गुजरात ने 19.4 ओवर में पांच विकेट पर 181 रन बनाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर की शुरुआत अच्छी नहीं रही। अजिंक्य रहाणे को मोहम्मद सिराज ने बिना खाता खोले पवेलियन भेजा। नंबर तीन पर उतरे अंगकृष रघुवंशी भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और वह 4 गेंदों में सिर्फ आठ रन बनाकर आउट हुए। टिम सीफर्ट भी 14 गेंदों का सामना करने के बाद 19 रन बनाकर आउट हुए। 32 के स्कोर पर तीन विकेट गंवाकर मुश्किल में दिख रही केकेआर की पारी को रोवमैन पॉवेल और कैमरून ग्रीन ने संभाला। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 55 रन जोड़े। पॉवेल 20 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हुए। अनुकूल रॉय सात गेंदों में नौ रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा का शिकार बने। रिंकू सिंह भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और वह महज एक रन बनाकर आउट हुए। रमनदीप सिंह ने आठ गेंदों का सामना करते हुए दो चौके और एक छक्के की मदद से 17 रन बनाए।

दी नेक्स्ट पोस्ट

स्वामी मुद्रक एवं प्रकाशक बृजेन्द्र कुमार द्वारा फाइन ऑफसेट प्रिन्टर्स मदरसा हुसैनिया बिल्डिंग बक्सीपुर गोरखपुर से मुद्रित एवं 665 बी गंगा टोला, निकट जानकी बिल्डिंग मैटेरियल बसारतपुर पश्चिमी, गोरखपुर से प्रकाशित। पिनः– 273003

UPHIN/2023/90814

बृजेन्द्र कुमार

मो0. नं0. 7307180148,9170772370

Email- thenextpost01@gmail.com

नोटः– समाचार पत्र से सम्बन्धित सभी वाद–विवाद गोरखपुर जिला न्यायालय के अन्तर्गत मान्य होंगे।

आईपीएल 2026 के बीच जर्मन मॉडल लिजलाज (स्प्रेंं) की फोटो लाइक करने को लेकर चर्चा में आए. सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें वायरल हुईं, जिसमें कोहली का लाइक जर्मन मॉडल की इंस्टाग्राम तस्वीर पर दिख रहा था. इसी तरह कोहली पिछले साल भारतीय एक्ट्रेस अवनीत कौर की तस्वीर लाइक करके चर्चा का विषय बने थे. बता दें कि बीते शुक्रवार कोहली के लाइक को लेकर चर्चा तेज हुई. हालांकि इस मामले पर कोहली ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन जर्मन मॉडल लिजलाज ने जरूर मामले पर चुप्पी तोड़ी. उन्हें कोहली के बुरा लगा. इसके अलावा उन्होंने कोहली के इरादे को लेकर भी बात की.

मॉडल लिजलाज ने क्या कहा?

हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए लिजलाज ने कहा, "यह पागलपन था क्योंकि मैं उठीं और मैं हर जगह न्यूज में थीं. मुझे नहीं पता कि उन्होंने कब फोटो लाइक की, मुझे न्यूज में यह पता चला. कई लोगों ने आर्टिकल देखे जो मुझपर अलग–अलग प्लेटफॉर्म पर हुए थे. मुझे बहुत सारे मैसेज आए, लोग इस बारे में उत्साहित थे."

'शायद उनका इरादा वो नहीं था...'

लिजलाज ने आगे कहा, "मुझे उनके लिए थोड़ा खराब लग रहा है. मैं बहुत खुश थीं कि उन्होंने फोटो लाइक की, लेकिन फिर उन्होंने अनलाइक कर दी. मुझे उनके लिए ठीक नहीं लगा क्योंकि यह इतनी बड़ी स्टोरी बन गई. लोगों ने कैसे ध्यान दिया, कैसे लोगों ने इसे न्यूज बना दिया. शायद इसके पीछे उनका वो इरादा नहीं था, लेकिन मैं फिर भी आभारी हूं. मैं उनकी तरफ से मिले सपोर्ट की सहराना करती हूं।